भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3455

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण व्यापार मालिकों का ई-कॉमर्स कौशल प्रशिक्षण

3455. श्री शशांक मणिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में ऐसे ग्रामीण उद्यमियों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं जो व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री जैसे ई-कॉमर्स कौशल में ग्रामीण व्यापार मालिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मौजूदा कार्यक्रम, यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त पहल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने व्यापक बाजार पहुंच के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के 2253 ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों में शामिल किया है।

उत्तर प्रदेश के 802 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की देशभर के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपेन नेटवर्क (ओएनडीसी) में शामिल किया गया।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्यमी स्वेच्छा से अपने व्यवसाय के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे होंगे, जिनके आकड़े केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार ने ग्रामीण व्यवसाय स्वामियों को ई-कॉमर्स कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसेः

- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है, ने भारतीय उद्यमशीलता ईकोसिस्टम में सहायता प्रदान करने के लिए 4 सितंबर, 2023 को मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)

पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य, आकांक्षी और मौजूदा लघु व्यवसाय स्वामियों को आवश्यक साधन, ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराना तथा उभरते एवं मौजूदा उद्यमियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित करना है। उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत लगभग 22,000 एनआईईएसबीयूडी प्रशिक्षुओं को मेटा द्वारा डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया गया है।

- एनआईईएसबीयूडी ने मेटा स्मॉल बिजनेस एकेडमी (एमएसबीए) के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग कौशल पर चार ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 8707 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला, ब्रांडिंग, पैकिंग, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करने आदि विषयों पर ई-कॉमर्स भागीदारों के साथ नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(ग) : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओडीओपी) की अग्रगामी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य, डिजिटल कॉमर्स को सभी के लिए उपलब्ध कराना है, जिससे कि प्रत्येक विक्रेता, एमएसएमई, व्यापारी, किसान और उपभोक्ता डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाएं, इसके भागीदार बनें और इसका लाभ उठा सकें। ओएनडीसी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों में शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- छोटे व्यवसायों की बाजार पहुंच का विस्तार करके उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तथा ओएनडीसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ओएनडीसी ने भारत के प्रत्येक गांव को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के नेटवर्क के साथ साझेदारी की है तथा ग्रामीण भारत में सहायक ई-कॉमर्स को बढ़ावा दे रहा है।
- लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता प्रदान करने के लिए ओएनडीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। 7000 से अधिक एफपीओ पहले ही ओएनडीसी में शामिल हो चुके हैं, जिससे वे भारत के 60 से अधिक शहरों में अपनी उपज का विक्रय करने में सक्षम हैं। यह पहल किसानों और एफपीओ उद्यमों को डिजिटल रूप से सशक्त करती है और उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान करती है।
- प्रसार भारती वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण भारत के लिए ओटीटी और ई-कॉमर्स

प्लेटफॉर्म के साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं को एकजुट करने के लिए ओएनडीसी के साथ कार्य कर रहा है। इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेव्स' पर खरीदारी को लागू करना शामिल है, जिसे ओनडीसी के डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया जाना है ताकि उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को लागू किया जा सके, जिससे ग्रामीण विक्रेताओं के लिए डिजिटल दूरी को कम किया जा सके।

- एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग (टीम) स्कीम शुरू की है, जिसे 5 लाख लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ओएनडीसी में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके 50% लाभार्थी महिला-स्वामित्व वाले उद्यम होंगे।
- ओनडीसी, सिडबी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), ग्रामीण, सत्व आदि जैसी लोकोपकारी एजेंसियों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल होने तथा ओनडीसी के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बना रहा है। बीएमजीएफ ने ओनडीसी के माध्यम से 1 मिलियन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया है।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को शामिल करने और विपणन के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों क्रमश: फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेजॉन, फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) और जियोमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में यात्रा बुकिंग उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एसएचजी सदस्यों की सहायता करने हेतु एक प्रारंभिक परियोजना संचालित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और ईजीट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****